देश का ग्रोथ इंजन बनने की राह पर आगे बढ़ा यूपी

आजादी के बाद पहली बार समग्र विकास पर फोकस करते हुए उत्तर प्रदेश अब देश का प्रमुख ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। बीते आठ साल के दौरान प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर की गई सख्ती ने अपराधियों में भय और निवेशकों में पैदा हुए विश्वास के चलते यूपी अब निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभरा है।

प्रदेश सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नियत और बेहतर नियोजन की वजह से प्रदेश की कानून-व्यवस्था को एक माडल के रूप में पूरे देश में देखा व सराहा जा रहा है। पुलिस सुधार हो, बुलडोजर फार्मूला हो या संवेदनशील मामलों में संवाद-सम्पर्क की नीति, हर मायने में उप्र ने अन्य राज्यों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और कानून के बुलंद इकबाल का ही प्रमाण है कि पहले जिनकी हैसियत सरकार बनाने-बिगाड़ने की हुआ करती थी, आज जेल में बंद अपने साम्राज्य को तिल-तिल ढहते हुए देखने को मजबूर हैं। मुख्तार अंसारी व अतीक अहमद कभी प्रदेश में आतंक

ए.के. जैन
पूर्व पुलिस महानिदेशक, उप्र

का पर्याय होते थे, इनके गुर्गे आये दिन कहीं हत्या, तो कहीं रंगदारी, कहीं जमीनों पर कब्जे करते थे। दूसरों की संपत्तियों पर अवैध कब्जा करना मानों इनका पहला कर्तव्य था, ऐसा सब राजनैतिक संरक्षण के बिना संभव न था।

वर्तमान सरकार में शासन स्तर पर जीरो टॉलरेंस की नीति घोषित करते हुए पुलिस-प्रशासन को जिस तरह स्थायित्व के साथ स्वायत्तता दी है, उसने प्रदेश की तस्वीर बदल दी है तथा उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है। महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में भी यूपी देश में प्रथम स्थान पर है। एनसीआरबी के मुताबिक कि वर्ष 2016 की तुलना में अपराधों में भी कमी आयी है।

आतंकवादी तत्वों पर सख्त निगरानी हेतु एटीएस को सशक्त किया गया है और देवबंद, बहराइच, अलीगढ़, अयोध्या, नोएडा आदि जिलों में नयी यूनिट और तीन महिला पीएसी वाहिनियां लखनऊ, गोरखपुर एवं बदायूं में स्थापित की गयी हैं। उप्र स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6 वाहिनियां भी गठित की गयी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 2017 के बाद 2 लाख 14 हजार विभिन्न पदों पर पुलिस में भर्तियां की गयी हैं तथा 1.49 लाख पदों पर प्रोन्नति प्रदान की गयी है। हाल में संपन्न हुई 60 हजार सिपाहियों की भर्ती ने एक नया मापदंड समस्त प्रदेशों के लिए स्थापित कर दिया है। भविष्य में होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष भी करीब 27 हजार भर्तियां, विभिन्न पदों के लिए पुलिस विभाग में आदेश दिए गए हैं।

सभी 75 जिलों में साइबर थाने खोल दिये गये हैं तथा साइबर सेल सक्रिय किए गए हैं। वर्ष 2017 की तुलना में 2024 में अभूतपूर्व सुधार करते हुए, यूपी 112 का रिस्पान्स टाइम 25 मिनट 42 सेकंड से 7 मिनट 24 सेकंड कर दिया गया है। मार्च 2017 से मार्च 2025 तक प्रदेश में दुर्दान्त अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान कुल 226 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये है एवं 8443 घायल हुए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत 25558 अभियोग पंजीकृत कर 79,984 अपराधी गिरफ्तार कर जेल भेजे गये हैं। 930 शातिर अभियुक्तों को रासुका के तहत भी निरुद्ध किया गया है।

प्रयागराज महाकुंभ 2025 के सफल संचालन ने जहां उप्र की प्रबंधन क्षमता पर अपनी मुहर लगाई है, वहीं अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा आदि तीर्थ स्थलों ने अपनी तेजी से बदलती सांस्कृतिक सामाजिक व आर्थिक ताकत का भी परिचय दिया है। स्नान के विशिष्ट अवसरों पर, प्रयागराज में एकत्रित भारी भीड़, वहां की प्रशासनिक व्यवस्थाओं और सुविधाओं का लाइव फीडबैक लेने के लिए अनेकों बार मुख्यमंत्री अपने आवास को वार-रूम के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ डटे रहे। इससे भी सीएम की दूरदर्शिता, निर्णय और नेतृत्व करने की क्षमता पुष्ट हुई है। देखा जाए तो प्रदेश की कानून-व्यवस्था में रिफार्म करके सरकार ने जो परफॉर्म किया है उसके लिए भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व का लोहा माना जाना चाहिए।